

प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक ०७ फरवरी, 2008

विषय- मा० उच्च न्यायालय नैनीताल के अधिष्ठान में 01 पद प्रमुख निजी सचिव, 01 पद मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी एवं 01 पद प्रोटोकॉल अधिकारी के अस्थायी निःसंवर्गीय पदों की निरन्तरता बढ़ाया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 443/xxxvi(1)/2007-234/2001 दिनांक 1 अगस्त, 2007 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के अधिष्ठान में शासनादेश संख्या- 19-एक(2) न्याय विभाग/2003 दिनांक 1 अगस्त, 2003 द्वारा सृजित प्रमुख निजी सचिव के एक अस्थायी निःसंवर्गीय पद एवं शासनादेश संख्या- 98- एक (2)/छत्तीस(1)/2005-234/2001 दिनांक 15-12-2005 एवं शासनादेश संख्या - 98-एक (2) / xxx vi(1)/2005-234/2001 दिनांक 16-12-2005 द्वारा सृजित/संशोधित मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी एवं प्रोटोकॉल अधिकारी के एक-एक अस्थायी निःसंवर्गीय पद के कार्यकाल को वर्तमान शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाएं, दिनांक 1-3-2008 से 28-2-2009 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- उक्त पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्यय के अनुदान संख्या- 04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-102-उच्च न्यायालय-03-उच्च न्यायालय-00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 1331/xxvii(5)/2008 दिनांक 4-2-2008 को प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(आर०डी०पालीवाल)
सचिव,

संख्या- 40 (1)/xxxvi(1)एक/08-234/2001 समदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड माजरा, देहरादून ।
- 2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
- 3- वित्त अनुभाग-5/कार्मिक अनुभाग/एन०आई०सी०/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव,